

THE DEPUTY CHAIRMAN :

No, I have no time today. I am not allowing association.

SHRI ASHIS SEN: I want to speak because a little more is needed. The Award was published on 30th of April and on 4th of May. I had written to the Finance Minister to see that it is implemented as quickly as possible. It has not been gazetted yet. The Government's decision was that the Award will be final and binding. So, there is no question of the Government going back on the point and that it should be implemented as quickly as possible. The Labour Minister should also take into account that it has not been gazetted as yet. What is the intention of the Government behind this? We would like to know that and see that it is not delayed too much. I associate with the Views expressed by Comrade Balaram.

**Alleged Misappropriation by the
Officials of the rural electrification
corporation**

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल) :
आदरणीय उपसभापति महोदय, धन्यवाद
कि मुझे आपने मौका दिया स्पेशल मेंशन
करने का ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रश पी०
ठाकुर) पीठासीन हुए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन
कारपोरेशन में जो घाघली चल रही है
इस बारे में सरकार की नजर खींचना
चाहता हूँ । हमारे यहां देश में अभी
भी हजारों लाखों ऐसे गांव हैं जहां अंधेरे
में रात गुजारनी पड़ती है लेकिन रूरल
इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन के जो सरकारी
अफसर हैं ये आला पैमाने पर हजारों
लाखों करोड़ों रुपये की घाघली चला रहे
हैं मैं दो चार मिसालें आपके सामने देना
चाहता हूँ जो अखबारों में भी आ चुकी हैं

एक तो इनका दफ्तर जो अभी डी०
डी०ए० बिल्डिंग में है यहां हर महीने
डढ़ लाख रुपया भाड़ा दिया जाता है।
फिर जाखों रुपया खर्च करके इन्होंने सी०
जी०ओ० काम्पलेक्स, लोदी रोड में वहां की
स्कोप बिल्डिंग में दफ्तर लिया है ।
साढ़ चार करोड़ रुपये अभी तक खर्च हो
चुके हैं लेकिन दफ्तर अभी तक बदला
नहीं है । रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन
के जो सी०एम०डी० हैं उसका यह कहना
है कि गृह जो यानी एंट्रालाजी अभी सही
नहीं है, इसलिए वे दफ्तर बदल नहीं रहे
हैं की इसी तरह से ये जब रेल से आये
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन में तो
इनका अपना एकोमोडेशन एंशियाड विलेज
में है लेकिन ये रेलवे का बंगला छोड़ते
नहीं हैं चूंकि गृह प्रवेश ठीक से
नहीं हुआ, काफी ज्यादा सुपरस्ट्रिंक्स में
विश्वास रखते हैं इसलिए पुराना भी नहीं
छोड़ रहे हैं और नये में भी नहीं जा रहे
हैं । इसकी वजह से आर०ई०सी० को
अस्सी हजार रुपया महीने रेलवे को देना
पड़ रहा है, लेकिन वह नहीं जा सकते
गृह की वजह से नहीं जा सकते हैं लेकिन
उनका जो फर्निचर है, पुराना सामान है
अन्य आर्टिकल हैं, वह वहां रखे हुए हैं ।

इसी तरह से गेस्ट हाऊस भी भाड़ा
देकर यह चला रहे हैं, जिसके लिए पंद्रह
हजार रुपया महीना देना पड़ रहा है,
जबकि जो इनका अपना खरीदा हुआ
गेस्ट हाऊस है, उसको वह इस्तेमाल नहीं
करते, वहां उनका सामान पड़ा है ।
वहां वह अपने पिट्टू लोगो को बसाये
हुए रखते हैं । इस तरह की घाघली की
जा रही है ।

इसी तरह ओवरटेक के बारे में भी
हजारों-लाखों रुपये ओवरटेक के नाम पर
जो आला अफसर हैं हमारे, वह बंटवारा
कर रहे हैं, हमारे गांव के लोगों को अंधेरे
में रख कर ।

काम के वक्त यह फ़ाल्स सर्टिफिकेट
देकर यहां तक जो प्रोजेक्ट बना नहीं,
लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीशन के नाम पर
एस०ई०वी० को रुपये का पेमेंट कर दिया
जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास रिपोर्ट

[श्री मोहम्मद सलीम]

बाधित करना पड़ेगा कि काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। एच०ई०पी० की हल से ताराब नहीं क्योंकि उन्हें काम न होने के बावजूद भी पैसा मिल रहा है। कावज में हल तरह से प्रोजेक्ट करके पैसा देव कर दिया जा रहा है।

इसी तरह से यह कम जब कर रहे हैं, तो कुछ सिपाही जो लोग हैं, उनके साथ भी इनका अच्छा रवैया है।

मैं मानकी नगर खींचना चाहता हूँ कि पिछली सरकार में बूटा सिंह जी जब होश मिनिस्टर थे और कल्पनाथ राय जी जब पावर के स्टेट मिनिस्टर थे, तो इन्होंने बुराना साहब, चीफ़ मेनेजिंग डायरेक्टर भाऊ भार०ई०सी० उन की जो कंस्टीट्यूएन्सी है, वहाँ लाखों रुपये खेच बिना था, चुनाव से ठीक पहले-पहले तबकि इलेक्ट्रिकल के बजाय इलेक्ट्रोनियम ठीक से हो और इस तरह से अपना बकसद पूरा होवा जाए। ठीक चुनाव से पहले-पहले लाखों रुपये इन दोनों की कंस्टीट्यूएन्सी में खर्च करके भेजा गया था।

खास करके कल्पनाथ राय जी की कंस्टीट्यूएन्सी में भाषा करोड़ रुपये खर्च करके जो टैक्सफार्म बिठाया गया, उसका सब तक कोई हिसाब नहीं है।

इसलिए मैं भाषकी नगर इस ओर खींचना चाहता हूँ कि ऐसे कई डील हैं। अभी भी एक डील होने जा रहा है। बूटा सिंह जी के लड़के के साथ गलत तरीके से होने जा रहा है।

धीनगी सुर्वकाभा-पाटील (महाराष्ट्र) : भाष नाम मत जीविए।

श्री मोहम्मद सलीम : मैं सरकार से माँग करता हूँ कि इनवेस्टिगेशन की जाए और अगर वह प्रकट हो है, जो रिपोर्ट, जैसे मजदूर में माई हुई है, अगर वह प्रकट कर रहे हैं, तो एक तरह तो जो रुपये की विलगुल सूट हो रही है, इसको बंद किया जाए, इनवेस्टिगेशन किया जाए

और अगर पाया जाए कि वह गलती कर रहे हैं या अगर इनवेस्टिगेशन की खास जरूरत हो, तो इनका सबादना किया जाए।

सम्यवाह।

Statement of som* officers of Jammu and Kashmir Administration regarding firing on Amoral procession of Mantri Md. Farooq

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir) : Mr. Vice-Chairman I am obliged to you for giving me this opportunity to make a special mention on the statement made by 137 officers, Secretaries, Professors and Doctors of Jammu and Kashmir with regard to the firing on the mourning procession of Maulana Farooq on the 21st May, 1990. The statement made by the Minister of State in the House is contradictory to the statement of the said high level officers of the Government of Jammu and Kashmir. They stated that the firing was "unprovoked. They have stated that the firing was resorted to indiscriminately on innocent citizens and mourners who were going with the coffin and many, many people died and the number given by the Minister of State as 27 is clearly incorrect. The number of persons who actually died is more than 109 and the number of persons who sustained injuries of a grievous nature is 302. In fact, more than that number is affected by the said firing which will come to light in due course of time. The firing was not the only incident according to the said statement* of the high level officers. They have enumerated a number of places where 'smaller-firing indiscriminately was resorted;

to. They have pointed out 1 P.M. that every person Iran* in Jammu aad yyWflifa was treated as hostile and